



CENTER FOR GLOBAL  
LIBERTY & PROSPERITY  
DEVELOPMENT POLICY BRIEFING PAPER

21 अक्तूबर, 2009

# जानलेवा समाजवाद Socialism kills

स्वामीनाथन एस. अंकलेसरिया अय्यर

*आर्थिक सुधारों में देरी के कारण भारत में हुई मानव हानि  
The Human Cost of Delayed Economic Reform in India*

THE CATO INSTITUTE  
1000 MASSACHUSETTS AVENUE, N.W., WASHINGTON D.C. 20001-5403  
WWW.CATO.ORG  
PHONE (202) 842-0200 FAX (202) 842-3490

## अध्ययन का सारांश

साम्यवाद के पतन की 20वीं वर्षगांठ जबकि पास आ रही है, यह जांचना लाजिमी सा हो गया है कि साम्यवाद को न अपनाकर भी सोवियत संघ के मॉडल से पूरी तरह से प्रभावित रहे भारत जैसे देशों को क्या नुकसान हुआ? 1947 में आजादी के तीन दशकों के बाद तक भारत ने अंतरराष्ट्रीय कारोबार से लाभ कमाने की बजाय आत्मनिर्भरता पर ही पूरा जोर दिया। भारत में उत्पादन के तमाम साधनों पर सरकार का नियंत्रण भी बढ़ता ही चला गया। इन नीतियों ने आर्थिक विकास की दर को प्रति वर्ष 3.5 फीसदी तक पहुंचा दिया। यह निर्यात के रुझान वाले एशियाई देशों की तुलना में कम थी और सामाजिक संकेतकों की प्रगति भी काफी धीमी थी। भारत में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर तो और भी कम 1.49 फीसदी प्रति वर्ष थी। इसने 1981 में प्रयोग के तौर पर आर्थिक सुधारों के लागू होते ही गति पकड़ ली। ताजा दशक में सुधारों के गहरी पैठ जमा लेने के बाद तो यह 6.78 फीसदी प्रति वर्ष तक पहुंच गई। अगर भारत ने एक दशक पहले ही आर्थिक

सुधारों को अपना लिया होता और तेजी से आर्थिक विकास के साथ वह मानव विकास सूचकांक में भी सुधार दिखाता तो उसका सामाजिक सूचकांकों पर क्या असर होता? यह लेख इसी बात का अनुमान लगाने का प्रयास करेगा कि सुधारों में देरी और आर्थिक विकास की धीमी गति और सामाजिक संकेतकों में धीमी गति से सुधार का "बच्चों की आबादी," "साक्षरता" और "गरीबों" की संख्या पर क्या असर पड़ा। पाया गया कि अगर सुधार पहले ही लागू कर दिए गए होते तो 1.45 करोड़ बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, 26.1 करोड़ ज्यादा भारतीय साक्षर होते और 1.09 करोड़ ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से ऊपर होते। यानि ये बच्चे, साक्षर और गरीबी रेखा के ऊपर के नागरिक जो आज "लापता" (Missing) हैं वे हमारे बीच हो हो सकते थे. आर्थिक सुधारों में देरी एक बड़ी सामाजिक त्रासदी का प्रतिनिधित्व करती है। इसका साफ अर्थ यही है कि भारत के समाजवाद के दौर ने जिस विकास के दावे किए थे, वह उनको पूरा कर पाने में नाकाम ही साबित हुआ।

*स्वामीनाथन एस. अंकलेसरिया अच्यर कैटो इंस्टीट्यूट के सेंटर फॉर ग्लोबल लिबर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी में रिसर्च फ़ैलो हैं और भारत के दो सबसे बड़े आर्थिक समाचार-पत्रों 'दि इकोनॉमिक टाइम्स' तथा 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' के संपादक रह चुके हैं.*

## प्रस्तावना (Introduction)

### भारत पर सोवियत संघ का भारी प्रभाव था

दुनिया जबकि साम्यवाद के पतन की 20वीं वर्षगांठ मना रही है, कई विश्लेषकों को याद होगा कि कैसे सोवियत नीतियों की नाकामी ने सरकार को उत्पादन पर ज्यादा अधिकार दे दिया था और साम्राज्यवादी जाल की संज्ञा देकर कैसे विदेश व्यापार और निवेश को हतोत्साहित किया जाता था। भारत जैसे विकासशील

देशों ने भी ऐसी ही नीतियों को अपनाया था, जो साम्यवादी नहीं समाजवादी थे। 1930 के दशक में सोवियत संघ द्वारा हासिल आर्थिक मजबूती का भारत कायल था। दरअसल वह दौर पश्चिमी देशों में महामंदी का था।

भारत को 1947 में जाकर आजादी मिली। 1950 में भारत ने पहले तीन दशक के लिए समाजवाद के लिहाज से योजनाएं तैयार कीं। इन नीतियों ने सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) विकास दर को 3.5 फीसदी और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर को 1.49 फीसदी तक पहुंचा दिया। 60 और 70 के दशक में पूर्वी एशियन टाइगरस (कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग) ने 7-8 फीसदी सकल राष्ट्रीय उत्पाद दर हासिल की। बाद में 'मिनी टाइगरस' के उपनाम से मशहूर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों (थाइलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया) ने भी 7-8 फीसदी की सकल राष्ट्रीय उत्पाद दर हासिल कर ली। इस तरह से भारत का समाजवाद सुस्त साबित हुआ। भारत की विश्व निर्यात में 1947 में आजादी के समय की 2.2 फीसदी की साझेदारी 1985 तक गिरकर 0.45 फीसदी हो गई, लेकिन समाजवादियों ने इसे आत्मनिर्भरता में कामयाबी के तौर पर देखा, जबकि वास्तविकता में यह कारोबार में भारी नुकसान था।<sup>1</sup>

भारत ने 1980 के दशक में सुधारों को काफी मंथर गति से लागू किया था, लेकिन 1991 के भुगतान संतुलन के संकट<sup>2</sup> के बाद यह मुख्यधारा की नीति बन गई। इसी साल सोवियत संघ के पतन ने भारतीय राजनीतिज्ञों को इस बात का अहसास करा दिया कि समाजवाद पर और जोर भारत को संकट से नहीं उबार पाएगा और चीन में दैंग शियाओपिंग के कामयाब बाजारोन्मुख सुधारों ने बता दिया था कि आर्थिक उदारीकरण के बेशुमार फायदे हैं। भारत की सुधार प्रक्रिया उत्तरोत्तर और अनियमित थी, लेकिन इसके संचित (cumulative) प्रभाव ने 2003-08 में भारत को चमत्कारी अर्थव्यवस्था बना दिया जहां सकल राष्ट्रीय उत्पाद की विकास

दर 9 फीसदी और प्रति व्यक्ति वार्षिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद विकास दर 7 फीसदी से ज्यादा हो गई। इसने आय और सामाजिक संकेतकों में भी सुधार दिखाया। अगर भारत ने आर्थिक सुधारों को एक दशक पहले लागू किया होता तो जीवन स्तर और सामाजिक संकेतक किस तरह से भिन्न होते? यह अध्ययन इस बात का अनुमान लगाता है कि बाल शिशु मृत्यु दर में कमी के कारण कितने बच्चों को बचाया जा सकता था, कितने और अधिक भारतीयों को साक्षर बनाया जा सकता था और कितने अधिक लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके होते। स्वाभाविक तौर पर, तथ्यों के विपरीत अनुमान सटीक नहीं हो सकते। लेकिन यह इस बात की कल्पना तो दे ही सकते हैं कि भ्रामक और दिशाहीन नीतियों के कारण कमजोर और गरीबों को किस त्रासदी का सामना करना पड़ा।

### साधारण अनुमानों की बात (The Case for Simple Estimates)

इतिहास हमें बताता है कि छोटे से परिवर्तनों का बड़ा और अनसोचा परिणाम हो सकता है। पास्कल की यह बात काफी ख्याति प्राप्त है कि अगर क्लियोपेट्रा की नाक थोड़ी छोटी होती तो दुनिया का इतिहास कुछ और होता। यानी तब वह उतनी खूबसूरत नहीं होती।<sup>3</sup> मार्क एंथोनी उसके प्यार में पागल नहीं होता, मार्क एंथोनी और ऑक्टेवियस के बीच गृहयुद्ध नहीं हुआ होता और रोमन ही नहीं पूरी दुनिया का इतिहास शायद अलग होता। फिर भी, क्लियोपेट्रा की नाक का सिद्धांत, अर्थशास्त्रियों या इतिहासकारों को 'क्या होता अगर' जैसे सवालों को उठाने से नहीं रोक सका और न ही कल्पना को खुली छूट देकर ऐसे सवालों के जवाब देने की कोशिशों को ही रोक जा सका।

उदाहरण के लिए, अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार पाने वाले अमर्त्य सेन ने विकासशील देशों में लिंगभेद के आधार पर 10 करोड़ "कम या लापता महिलाओं" ("Missing Women") के अपने भाव को लोकप्रिय बना डाला।<sup>4</sup> उन्होंने इस अनुमान को लोकप्रिय बनाने में भी काफी कोशिशें कीं कि 1958-61 के दौरान माओ की 'ग्रेट लीप फॉरवर्ड' की गलत नीतियां तीन करोड़ चीनियों की मौत का कारण बनीं।<sup>5</sup> यहां सेन की 'लापता महिलाओं' ("Missing Women") पर आधारित अनुमान लगाने की तकनीक का खुलासा जरूरी सा हो गया है:

लापता महिला और पुरुष के विभिन्न अनुपातों के संख्यात्मक विचार के लिए हम किसी देश में महिलाओं की कमी का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे चीन या भारत, हम चीन या भारत में और अतिरिक्त महिलाओं की संख्या का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि

यहां पर भी अगर दुनिया के अन्य इलाकों (महिला-पुरुष अनुपात भी वहां के बराबर होता) की तरह खयाल रखा जाता तो यहां महिलाओं की संख्या कितनी और ज्यादा होती। अगर हम पुरुषों और महिलाओं की समान आबादी की कल्पना करें तो दक्षिण एशिया, पश्चिमी एशिया और चीन में महिलाओं का पुरुषों के साथ 0.94 का अनुपात इस बात का इशारा करेगा कि महिलाओं की संख्या 6 फीसदी कम है। लेकिन पुरुष और महिलाओं का एक सा खयाल रखने वाले देशों में महिला-पुरुष अनुपात 1.05 का है तो वास्तविकता में महिलाओं की कमी 11 फीसदी हो जाती है। अगर 1.05 को अनुपात का आधार मान लिया जाए तो अकेले चीन में ही 5 करोड़ लापता या कम महिलाएं हैं। जब यह संख्या दक्षिणी एशिया, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका की ऐसी ही संख्या में जोड़ दी जाती है तो 10 करोड़ महिलाओं की कमी उभरकर सामने आ जाती है। यह आंकड़े हमें बताते हैं कि महिलाओं को कितनी उपेक्षा का सामना करना पड़ा जोकि उनके लिए घातक साबित हुआ।<sup>6</sup>

काम की ऐसी पद्धति जहां साधारण है वहीं आलोचनाओं के लिहाज से भी आसान है। यह महिला मृत्यु दर पर अन्य प्रभावों का जिक्र नहीं करती। *फ्रीकोनॉनॉमिक्स* के विख्यात लेखकों स्टीफन जे. डुबनर और स्टीवन डी. लेविट ने एक वैकल्पिक खुलासा पेश किया है, जिसका पहला जिक्र शिकागो यूनिवर्सिटी की अर्थशास्त्री एमिली फॉस्टर ने किया था।<sup>7</sup> उसका कहना था कि एशियाई देशों में लड़कों की ऊंची जन्म दर का कारण कन्या भ्रूण हत्या (और भेदभाव के अन्य कारण) नहीं बल्कि गर्भवती महिलाओं को होने वाला हेपेटाइटिस बी है।<sup>8</sup> मोनिका दास गुसा जैसे स्कॉलर्स का कहना है कि ओस्टर ने बात का बतंगड़ बना दिया है। चीन में अगर पहला शिशु लड़की है तो दूसरा लड़का ही होने की संभावना ज्यादा है, यह साफ तौर पर हेपेटाइटिस बी की बजाय लैंगिक भेदभाव की ओर ही इशारा करता है।<sup>9</sup> जनसंख्या के आंकड़ों के एक अन्य विश्लेषक एंसली कोल ने सेन के विश्लेषण की सावधानीपूर्वक की गई समीक्षा के बाद महिलाओं की संख्या में कमी का अनुमान 100 मिलियन (10 करोड़) की बजाय 60 मिलियन (6 करोड़) होने का लगाया है।<sup>10</sup> लैंगिक भेदभाव के अलावा किसी भी समाज में अन्य कारण भी लड़के और लड़कियों के जन्म की संख्या को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए "कम या लापता महिलाओं" को लेकर अनुमान में अनिश्चितता तो होना ही है। फिर भी ऐसे आंकड़ों की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। सेन का विश्लेषण आसान शब्दों में लैंगिक भेदभाव के कारण संभावित सामाजिक भेदभावों की ओर इशारा करता है। यहां मुख्य बात आंकड़ों की सुस्पष्टता

नहीं, बल्कि सामाजिक संकट का आकार है। सेन के आंकलन को पूरी दुनिया में इस विषय पर बहस के दौरान इस्तेमाल किया जाता रहा है। उनका "महिलाओं की कमी" या missing women ऐसी चर्चाओं के लिए ब्रह्मवाक्य की तरह हो गया है। जांच-पड़ताल के इसी सिलसिले को आगे

## भारत के समाजवाद ने उसे एशिया का पिछड़ा बनाया

बढ़ाते हुए-बिना सेन को इसमें लिप्त किए-में भारत में "बच्चों की आबादी," "साक्षरता" की कमी और "गरीबों" की अधिकता के आंकलन की कोशिश करूंगा। शिशु मृत्यु दर, साक्षरता और गरीबी के कई कारण होते हैं। हर कारण के प्रभाव को माप पाना मुश्किल होता है।

सेन जब "महिलाओं की कमी" की बात करते हैं तो आंकलनों में अनिश्चितता का मुख्य कारण यही होता है। फिर भी मैं देरी से लागू किए गए आर्थिक सुधारों के कारण सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) के धीमे विकास के सामाजिक प्रभाव का आंकलन करने की कोशिश करूंगा।

## कार्यपद्धति (Methodology)<sup>11</sup>

भारत में 1980 तक जीएनपी की विकास दर कम थी, लेकिन 1981 में आर्थिक सुधारों के शुरू होने के साथ ही इसने गति पकड़ ली थी।<sup>12</sup> 1991 में सुधार पूरी तरह से लागू होने के बाद तो यह मजबूत हो गई थी। 1950 से 1980 के तीन दशकों में जीएनपी की विकास दर केवल 1.49 फीसदी थी। इस कालखंड में सरकारी नीतियों का आधार समाजवाद था। आयकर की दर में 97.75 फीसदी तक का इजाफा देखा गया। कई उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सरकार ने अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से नियंत्रण के प्रयास और अधिक तेज कर दिए थे। 1980 के दशक में हल्के से आर्थिक उदारवाद ने प्रति व्यक्ति जीएनपी की विकास दर को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 2.89 कर दिया। 1990 के दशक में अच्छे-खासे आर्थिक उदारवाद के बाद तो प्रति व्यक्ति जीएनपी बढ़कर 4.19 फीसदी तक पहुंच गई। 2001 में यह 6.78 फीसदी तक पहुंच गई। क्या होता अगर आर्थिक सुधार कुछ अरसे पहले से लागू कर दिए जाते? 1950 में जब भारत ने 3.5 फीसदी की विकास दर हासिल कर ली थी तो कई अर्थशास्त्रियों ने इसे ब्रिटिश राज के अंतिम 50 सालों की विकास दर से तिगुना हो जाने का जश्न मनाया था। समाजवादियों ने इसे भारत की आर्थिक नीतियों की जीत करार दिया था, वे नीतियां जो अंतर्मुखी थीं और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के वर्चस्व वाली थीं। हालांकि 1960 के दशक में ईस्ट इंडियन टाइगरों (दक्षिण कोरिया, ताईवान, सिंगापुर और हांगकांग) ने भारत से दोगुनी विकास दर हासिल कर ली थी।

जो इस बात का प्रमाण था कि उनकी बाह्यमुखी और निजी क्षेत्र को प्राथमिकता देने वाली आर्थिक नीतियां बेहतर थीं। ऐसे में भारत के पास 80 के दशक की बजाय एक दशक पहले 1971 में ही आर्थिक सुधारों को अपनाने के लिए एक अच्छा उदाहरण मिल चुका था।

यह अध्ययन यही पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्या होता अगर आर्थिक सुधार 1971 से ही लागू कर दिए गए होते। इससे पता चलता है कि एक-एक दशक बाद हासिल की जा रही जीएनपी की विकास दर एक-एक दशक पहले ही हासिल कर ली गई होती। परिदृश्य कुछ ऐसा होता कि 1980 के दशक में हासिल जीएनपी विकास दर (2.89 फीसदी प्रतिवर्ष) 1970 के

दशक में ही हासिल कर ली गई होती, 1990 के दशक में हासिल जीएनपी विकास दर (4.19 फीसदी प्रतिवर्ष) 1980 के दशक में ही हासिल कर ली गई होती, 21वीं सदी में हासिल जीएनपी विकास दर (6.78 फीसदी प्रतिवर्ष) 1990 के दशक में ही हासिल कर ली गई होती। मैं 21वीं सदी में

भारत हर हाल में 1971 में आर्थिक उदारीकरण शुरू कर सकता था, असल प्रक्रिया शुरू होने से एक दशक पहले.

और अधिक जीएनपी विकास दर का अनुमान नहीं लगाता। यह अनुदार आंकलन उस वक्त हासिल की जा सकने वाली जीएनपी विकास दर के दायरे में ही है। अब हम सवाल उठा सकते हैं कि तीन प्रमुख मापदंडों-शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और गरीबों की संख्या में आर्थिक सुधार जल्द लागू होने का क्या असर पड़ता?

भारत के आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर मैं इन तीनों मापदंडों की प्रति व्यक्ति जीएनपी (या प्रति व्यक्ति जीएनपी में परिवर्तन के सापेक्ष हर मापदंड में परिवर्तन दर) मूल्य सापेक्षता (Elasticity) की गणना करूंगा। और फिर इस मूल्य सापेक्षता के आधार पर मैं इस बात का आंकलन करने का प्रयास करूंगा कि आय और सामाजिक बेहतरी के साथ अगर आर्थिक सुधार एक दशक पहले आए होते तो स्थिति कितनी भिन्न होती। खासतौर पर मैं ऊंची विकास दर की परिस्थितियों में आंकलन करता कि,

(अ) 1971 से 1980 के दौरान कितने कम शिशुओं की मौत हुई होती.

(ब) हर साल कितने अधिक लोग साक्षर हुए होते और

(स) कितने अधिक लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए होते। ऊंची विकास दर के इस आंकलन और वास्तविक परिणामों का अंतर हमें उन लोगों की संख्या का अनुमान दे देता, जो

इन सब बातों से वंचित रह गए।

## जल्द सुधार और तेज विकास के अनुमान पर प्रति व्यक्ति विकास

### Per capita growth, Assuming Earlier Reforms and Faster Growth

पहले कदम के तौर पर मैं पिछले भाग में ही समझा दी गई कार्यपद्धति से जल्द सुधार लागू करने और तेज विकास की परिस्थितियों में प्रति व्यक्ति जीएनपी का आंकलन करूंगा। इस परिस्थिति में विकास दर को वह माना जा रहा है जो अगले दशक में हासिल की गई। टेबल 1

सुधार प्रक्रिया में देरी की वजह से हुई शिशुओं की मृत्यु को बड़े पैमाने पर घटित मानव त्रासदी कह सकते हैं।

विस्तृत जानकारी देती है। तेज सुधारों के कारण 1999-2000 के मूल्यों के आधार पर 2008 में प्रति व्यक्ति जीएनपी वास्तविक 28,970 रूपए (579 डॉलर) की बजाय 54460 रूपए (1089 डॉलर) होती।<sup>13</sup> 2001-2008 के लिए टेबल 6.78 फीसदी की विकास दर का अनुमान लगाता

है, दर जो 2001-2006 में हासिल की गई। 2005 से 2007 के बीच प्रति व्यक्ति जीएनपी विकास दर ज्यादा तेज (7-8 फीसदी) थी। लेकिन मैं इस दशक के लिए 6.78 फीसदी का अनुमान लगाता हूँ। इस बात को देखते हुए कि वैश्विक मंदी बाकी के दशक की विकास दर को कम कर देगी।

## जल्द सुधारों का शिशु मृत्यु दर पर प्रभाव

### The Impact of Early Reforms on Infant Mortality

भारत की शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate या आईएमआर) में 1971 की 132 मृत्यु प्रति एक हजार जन्म से 2008 तक 58 मृत्यु प्रति एक हजार जन्म तक की गिरावट दर्ज की गई। 37 साल की इस अवधि में आईएमआर में कमी की, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में इजाफे से मूल्य सापेक्षता (elasticity) -0.82 रही। यानी कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हर एक फीसदी की बढ़ोतरी आईएमआर में 0.82 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। इसी मूल्य सापेक्षता के आधार पर मैं तेजी से विकास और जल्द सुधार लागू करने वाली परिस्थितियों में शिशु मृत्यु दर की कल्पना टेबल 2 में करता हूँ। इससे हमें वर्ष-दर-वर्ष उन बच्चों की गणना

टेबल-2 तीव्र सुधारों की दशा में प्रति व्यक्ति जीएनपी का अनुमान					तीव्र सुधार परिदृश्य: प्रति व्यक्ति जीएनपी, रु. (सैकड़ा)
प्रति व्यक्ति जनसंख्या (दस लाख या मिलियन्स)	जीएनपी, रु. (सैकड़ा)	दशक में औसत सालाना बढ़ोतरी	तीव्र सुधार, तेज विकास परिदृश्य		
1971	548	85.8	1971-1980 के लिए 1.49%	1971-1980 के लिए 2.89%	85.8
1972	562	83.6			88.2
1973	575	85.5			90.8
1974	589	84.7			93.4
1975	602	90.3			96.1
1976	616	89.6			98.9
1977	629	94.2			101.8
1978	643	97.3			104.7
1979	656	90.2			107.7
1980	670	94.5			110.9
1981	683	97.8	1981-1990 के लिए 2.89%	1981-1990 के लिए 4.19%	115.5
1982	700	98.1			120.3
1983	716	103.6			125.4
1984	732	105.1			130.6
1985	749	107.2			136.1
1986	765	109.5			141.8
1987	781	110.7			147.7
1988	797	119.0			153.9
1989	814	123.7			160.4
1990	830	127.3			167.1
1991	846	126.5	1991-2000 के लिए 4.19%	1991-2000 के लिए 6.78%	178.4
1992	865	130.6			190.5
1993	883	135.5			203.5
1994	901	141.4			217.3
1995	919	148.7			232.0
1996	938	157.8			247.7
1997	956	161.9			264.5
1998	974	169.3			282.5
1999	992	176.9			301.6
2000	1010	180.8			322.1
2001	1029	187.7	2001-2006 के लिए 6.78%	2001-2008 के लिए 6.78%	344.0
2002	1047	192.3			367.3
2003	1065	205.5			392.2
2004	1083	217.4			418.8
2005	1102	234.7			447.2
2006	1120	254.0			477.6
2007	1138	273.7			510.0
2008	1156	289.7			544.6

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान, भारत सरकार, महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त कार्यालय.

नोट: प्रति व्यक्ति जीडीपी 1999-2000 के स्थिर मूल्य पर है. जनगणना कैलेंडर वर्ष के आधार हर दस साल में एक बार दर्ज होती है. सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) की गणना 1 अप्रैल से 30 मार्च के बीच राजस्व वर्ष के आधार पर होती है. तालिका में किसी भी सूचीबद्ध वर्ष के लिए आंकड़ा, जैसे 1971 के लिए 1971 कैलेंडर वर्ष में जनगणना और 1971-72 में प्रति व्यक्ति जीएनपी दर्शाता है. आंकड़ों को सामान्य औसत के जरिये जनगणनाओं/एनएसएसओ सर्वेक्षणों के बीच के वर्षों के लिए बहिर्वेशित (extrapolated) किया गया है.

**टेबल-2 भारत के “लापता बच्चे” (India’s “Missing Children”)**

शिशु मृत्यु दर आइएमआर/1000		आइएमआर/1000 उच्च विकास दर के साथ	जन्मे शिशु (दस लाख या मिलियन्स)	सुधारों में देरी के कारण मृत अतिरिक्त शिशु (मिलियन्स)	सुधारों में देरी के कारण जुड़ती हुए अतिरिक्त शिशु मृत्यु (मिलियन्स)
1971	132		20.2		
1972	139	129	20.5	0.2	0.2
1973	134	126	20.8	0.2	0.4
1974	126	123	21.1	0.1	0.4
1975	140	120	21.4	0.4	0.9
1976	129	117	21.7	0.3	1.2
1977	130	114	22.0	0.3	1.5
1978	127	112	22.3	0.3	1.8
1979	120	109	22.6	0.3	2.1
1980	114	106	22.9	0.2	2.3
1981	110	103	23.2	0.2	2.4
1982	105	99	23.3	0.2	2.6
1983	105	96	23.5	0.2	2.8
1984	104	92	23.7	0.3	3.1
1985	97	89	23.9	0.2	3.3
1986	96	86	24.1	0.2	3.5
1987	95	83	24.2	0.3	3.8
1988	94	80	24.4	0.3	4.1
1989	91	78	24.6	0.3	4.4
1990	80	75	24.8	0.2	4.6
1991	80	71	25.0	0.2	4.8
1992	79	67	25.0	0.3	5.1
1993	74	63	25.1	0.3	5.4
1994	74	60	25.2	0.4	5.7
1995	74	56	25.3	0.5	6.2
1996	72	53	25.4	0.5	6.7
1997	72	50	25.5	0.6	7.2
1998	72	47	25.5	0.6	7.9
1999	70	45	25.6	0.6	8.5
2000	68	42	25.7	0.7	9.2
2001	66	40	25.8	0.7	9.9
2002	60	38	25.9	0.6	10.4
2003	59	36	26.0	0.6	11.0
2004	58	34	26.1	0.6	11.7
2005	58	32	26.1	0.7	12.4
2006	57	30	26.2	0.7	13.1
2007	55	28	26.3	0.7	13.8
2008	53	27	26.4	0.7	14.5

स्रोत: महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त. नोट: पूर्णन (rounding) के कारण कुछ योगफल नहीं जुड़ सकेंगे. कुल शिशुओं का अनुमान जनसंख्या और जन्म संबंधी आंकड़ों के आधार पर लगाया गया है.

में आसानी हो जाती है, जिनकी सुधारों में देरी के कारण मृत्यु हो गई। सुधारों में देरी के कारण काल का ग्रास बने बच्चों की कुल संख्या 1.45 करोड़ बनकर सामने आती है। इसे बड़ी मानवीय त्रासदी ही करार दिया जा सकता है।

## तेज विकास का साक्षरता पर असर

### The Impact of Faster Growth on Literacy

भारत हर दस वर्ष में जनगणना के दौरान साक्षरता दर के पर स्पष्ट आंकड़े हासिल करता है। साक्षरता दर से मतलब छह वर्ष से ऊपर के लोगों का अनुपात जो पढ़-लिख सकते हैं। मैं जनगणना के इन आंकड़ों की मदद से साक्षरता दर और 2001 के बाद जनगणनाओं के बीच साक्षरों की पूर्ण संख्या हासिल करता हूं। 1971 से 2008 के बीच प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद विकास की तुलना में साक्षरता में सुधार की मूल्य सापेक्षता 0.56 थी। यानी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हर एक फीसदी की बढ़ोतरी के साथ साक्षरता में 0.56 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी मूल्य सापेक्षता को तेजी से विकास के परिदृश्य पर लागू करने पर हर साल साक्षरता दर और साक्षरों की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। इस सारी मशक्कत का निचोड़ यह है कि अगर सुधारों को जल्द लागू किया जाता और विकास की दर भी तेज होती तो भारत में 2007 तक 100 फीसदी साक्षरता हो जाती। साथ ही यहां 2008 तक 26.1 करोड़ (261 मिलियन) ज्यादा साक्षर होते (देखें टेबल 3)। यह एक बहुत बड़ी संख्या है, दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा।<sup>14</sup> तेजी से विकास का परिदृश्य हमें पूरे कालखंड में एक समान मूल्य सापेक्षता दिखाता है। हकीकत में, जीएनपी की विकास दर के अलावा अन्य खामियों और कई कारकों के प्रभाव के कारण मूल्य सापेक्षता तो अस्थिर है। तेजी से विकास के परिदृश्य की औसत मूल्य सापेक्षता की तुलना में 1970 के दशक की वास्तविक साक्षरता की मूल्य सापेक्षता, ज्यादा थी। टेबल तीन में इसीलिए तेजी से विकास के परिदृश्य में 1970 के दशक में साक्षरों की संख्या में गिरावट देखने को मिलती है। निम्न आधार का प्रभाव (low-base effect) साफ देखा जा सकता है: छोटे से आधार से विकास बड़े आधार से किए गए विकास की तुलना में ज्यादा तेज लगता है, लेकिन अन्य मापदंडों का भी अध्ययन करने के बाद यह सोच निराधार साबित होती है। 1971-1981 के दशक में, साक्षरता में 37 फीसदी से 46 फीसदी तक का सुधार देखा गया, यानी 9 प्रतिशतता अंक (percentage point) की बढ़त या 9.4 करोड़ साक्षरों का इजाफा देखा गया। 1991-2001 के दशक में साक्षरता 1991 की 52.2

फीसदी की तुलना में 2001 में 64.8 हो गई, यानी 12 फीसदी प्रतिशतता अंक या साक्षरों में 20.6 करोड़ का इजाफा। प्रतिशतता अंक और साक्षरों की संख्या जैसे मापदंडों की बात की जाए तो 1990 का दशक साक्षरता के लिहाज से 1970 के दशक से बेहतर रहा।

## तेज विकास का गरीबी घटाने पर प्रभाव

### The Impact of Faster Growth on Poverty Reduction

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान (national sample survey organization) गरीबों की संख्या का अनुपात (poverty headcount ratio) यानी गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों की संख्या (the proportion of people below the poverty line) का पता लगाने के लिए हर पांच या छह साल में घर-घर जाकर सर्वेक्षण करता है। मैं साधारण औसत की मदद से सर्वेक्षणों के बीच के वर्षों के अनुपात के आंकलन करता हूँ। जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं, उसमें गरीबों की संख्या के अनुपात की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद की तुलना में मूल्य सापेक्षता -0.68 है। यानी, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हर एक फीसदी की बढ़ोतरी के साथ गरीबी में 0.68 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। इसी मूल्य सापेक्षता को तेज विकास के परिदृश्य पर लागू करने पर उन अतिरिक्त लोगों की गणना की जा सकती है जो एक दशक पहले सुधार लागू होने की स्थिति में गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए होते। (देखें टेबल 4)

टेबल 4 दिखाता है कि सुधारों को लागू करने में देरी ने 10.9 करोड़ (109 मिलियन) ज्यादा लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे रखा। यहां यह बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जहां गरीबों की संख्या का अनुपात गिरा तो वहीं दूसरी ओर आबादी में भी इजाफा हुआ। परिणाम यह हुआ कि तीन दशक के बाद भी गरीबों की संख्या में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। (1971 में यह 30.9 करोड़ थी तो 2004 में 298 करोड़)। अगर भारत ने जल्द सुधार लागू कर दिए होते और उसे तेज विकास का भी लाभ मिलता तो शायद गरीबों की संख्या में 1971 की 30.9 करोड़ से 2004 में 19.7 करोड़ तक की भारी कमी देखने को मिलती और गरीबों की संख्या में यह कमी 2008 तक संभवतया 17.4 करोड़ तक हो जाती। इसका मतलब होता 1971 से 2008 के बीच गरीबों की संख्या में 13.5 करोड़ की भारी कमी देखने को मिलती।

क्या आंकलन सत्य के करीब हैं?

(Are the Estimates Plausible?)

में तेज विकास के विरोधाभासी आंकलन के लिए बहुत ही सामान्य सी कार्यपद्धति इस्तेमाल करता हूं। उदाहरण के लिए यह तेज विकास की स्थिति में आबादी में किसी परिवर्तन का अनुमान नहीं लगाती। अन्य बातों को स्थिर रखा जाए तो शिशु मृत्यु दर में गिरावट आबादी में इजाफे का कारण बनेगी। दूसरी ओर तेजी से विकास से महिलाओं में साक्षरता दर और समृद्धि भी बढ़ेगी, यही दो कारक हैं जो कुल जन्मदर को कम करके आबादी को कम करते हैं। मैं तेज विकास के सामाजिक परिणामों के चक्र पर चर्चा का प्रयास नहीं कर रहा हूं। उदाहरण के लिए, आय में इजाफे से अपर्याप्त सरकारी सुविधाओं की तुलना में निजी क्षेत्र से शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग में इजाफा होता है, यहां तक कि गरीबों की ओर से भी। सुधार की किसी भी प्रक्रिया में खामियां, अनसोचे उतार-चढ़ाव और अन्य जटिल कारक होते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की तेज विकास दर कर राजस्व में इजाफा करती है और इस तरह से शिक्षा और

स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में मदद करती है। साक्षरता और शिशु मृत्यु दर (सरकारी पैसे के बेकार चले जाने के बाद भी) में सुधार देखने को मिलता है। इस अध्ययन में मेरा सीमित उद्देश्य सुधारों में देरी के कारण हुई सामाजिक त्रासदी को उजागर करना है। क्या आंकलन सत्य के करीब

आर्थिक उदारीकरण देरी से शुरू होने की वजह से 10.9 करोड़ अतिरिक्त लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए.

हैं? तेजी से विकास के परिदृश्य में शिशु मृत्यु दर 1971 की 132 प्रति हजार जन्म से, 2008 में 27 मौत प्रति हजार जन्म तक गिर जाती है। वास्तविक गिरावट 53 मौत प्रति एक हजार जन्म है। तेज विकास के दौर में 37 साल में शिशु मृत्यु दर में 80 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखी जाती है। तुलना की जाए तो दक्षिण कोरिया में 1960 (जब वहां पर सुधार शुरू किए गए थे) में 90 मौत प्रति एक हजार जन्म को 1995 तक 6 मौत प्रति एक हजार जन्म तक गिरा दिया था, यानी कि 35 साल में 93 फीसदी की गिरावट। मेरे सकल राष्ट्रीय उत्पाद विकास और शिशु मृत्यु दर में कमी के संभावित आंकलन दक्षिण कोरिया के वास्तविक आंकड़ों से कम हैं। इस लिहाज से "बच्चों की संख्या में कमी" (missing children) का आंकलन काफी अनुदार दिखाई देता है। साक्षरता के लिए तेज विकास का आंकलन पूरे कालखंड में 0.56 के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद से साक्षरता की स्थायी मूल्य सापेक्षता के आधार पर किया गया है। इसे किसी लिहाज से तेज नहीं कहा जा सकता। वास्तविकता में तो 1971 से 1986 के

**टेबल-3 भारत के “लापता साक्षर” (India’s “Missing Literates”)**

साक्षरता दर (%) 6 + आयु वर्ग के लिए	साक्षरों की संख्या (दस लाख या मिलियन्स)	तीव्र विकास के साथ साक्षरता दर %	तीव्र विकास के साथ साक्षरों की संख्या (मिलियन्स)	पूर्व में सुधार लागू हो जाते तो अतिरिक्त साक्षर (मिलियन्स)	
1971	37.0				
1972	37.9	164	37.6	163	-1.32
1973	38.8	173	38.2	170	-2.67
1974	39.7	182	38.8	178	-4.05
1975	40.6	191	39.4	185	-5.45
1976	41.5	200	40.1	193	-6.87
1977	42.4	210	40.7	201	-8.30
1978	43.3	219	41.4	210	-9.74
1979	44.2	229	42.0	218	-11.80
1980	45.1	239	42.9	227	-12.63
1981	46.0	250	43.7	237	-12.40
1982	46.6	260	44.7	249	-10.51
1983	47.2	270	45.8	262	-8.38
1984	47.9	281	46.8	275	-5.97
1985	48.5	291	47.9	288	-3.29
1986	49.1	302	49.1	302	-0.31
1987	49.7	313	50.2	316	2.97
1988	50.3	325	51.4	331	6.58
1989	51.0	336	52.6	346	10.53
1990	51.6	348	53.8	362	14.83
1991	52.2	359	55.8	384	24.85
1992	53.5	378	57.9	409	31.48
1993	54.7	397	60.1	436	38.99
1994	56.0	416	62.4	464	47.45
1995	57.3	436	64.7	493	56.93
1996	58.5	456	67.2	524	67.51
1997	59.8	477	69.7	556	79.25
1998	61.1	498	72.4	590	92.24
1999	62.3	520	75.1	626	106.56
2000	63.6	542	77.9	662	122.29
2001	64.8	565	80.9	704	139.54
2002	66.1	588	83.9	746	158.38
2003	67.4	611	87.1	790	178.92
2004	68.6	635	90.4	837	201.27
2005	69.9	660	93.8	885	225.52
2006	71.2	685	97.3	936	251.81
2007	72.4	710	100.0	981	271.23
2008	73.7	736	100.0	997	261.00

स्रोत: महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय. नोट: साक्षरता दर उन लोगों का समानुपात है जो छह वर्ष से ज्यादा आयु के हैं और जो पढ़-लिख सकते हैं. 1991-2001 में औसत परिवर्तन के आधार पर 2001 के बाद से साक्षरता दरों का अनुमान लगाया जाता है. आंकड़ों का हमेशा पूर्णन (rounding) के कारण योग नहीं किया जा सकता.

**टेबल - 4 भारत के “लापता, जो गरीब नहीं” (India’s “Missing Non-poor”)**

इस समूह में लोगों की संख्या का अनुपात (Headcount ratio) (%)		गरीबी रेखा से नीचे लोग (दस लाख या मिलियन्स)	तेज विकास की दशा में हैडकाउंट रेश्यो (%)	तेज विकास की दशा में गरीबी रेखा से नीचे लोग (मिलियन्स)	तेज विकास के साथ कमतर लोगों की संख्या (मिलियन्स)
1971	56.3	309			
1972	55.6	312	55.2	310	2
1973	54.9	316	53.9	311	5
1974	54.0	318	53.0	312	6
1975	53.1	320	52.0	313	7
1976	52.2	321	51.0	314	7
1977	51.3	323	50.0	314	9
1978	50.2	323	49.0	315	8
1979	49.0	322	48.0	315	7
1980	47.9	321	47.1	315	6
1981	46.8	320	45.7	312	8
1982	45.6	319	44.4	311	8
1983	44.5	318	43.1	309	10
1984	43.1	315	41.9	307	8
1985	41.7	312	40.7	305	7
1986	40.3	308	39.5	302	5
1987	38.9	304	38.4	304	3
1988	38.4	306	37.3	298	8
1989	37.9	308	36.3	295	13
1990	37.4	311	35.2	292	18
1991	36.9	313	33.6	284	28
1992	36.5	315	32.0	277	38
1993	36.0	318	30.6	270	48
1994	35.2	317	29.1	263	55
1995	34.4	317	27.8	255	61
1996	33.7	316	26.5	248	67
1997	32.9	314	25.3	242	73
1998	32.1	313	24.1	235	78
1999	31.4	311	23.0	228	83
2000	30.6	309	21.9	222	87
2001	29.8	307	20.9	215	92
2002	29.0	304	19.9	209	95
2003	28.3	301	19.0	203	98
2004	27.5	298	18.1	197	101
2005	26.7	294	17.3	191	104
2006	26.0	291	16.5	185	106
2007	25.2	287	15.7	179	108
2008	24.4	282	15.0	174	109

स्रोत: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान. आंकड़ों का हमेशा पूर्णन (rounding) के कारण योग नहीं किया जा सकता.

बीच साक्षरता में सुधार की दर इससे तेज थी। केवल 1986 के बाद ही तेज विकास के परिदृश्य ने इस दर को और अधिक ऊंचा किया। इसीलिए यह आंकलन अनुदार दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि अगर भारत ने सुधारों को पहले ही लागू कर दिया होता तो 2007 तक 100 फीसदी साक्षरता हासिल की जा सकती थी। अंत में, तेज विकास के आंकलन बताते हैं कि गरीबी की दर 1971 के 56.3 फीसदी से 2008 में 15 फीसदी तक गिर सकती थी। जबकि 2004 के सर्वेक्षण के अनुसार यह 27.5 फीसदी रही और 2008 का संभावित लक्ष्य 24.4 फीसदी का था।<sup>15</sup> केवल विकास को ही सबकुछ नहीं मानने वाले जोसेफ स्टिगलिट्ज जैसे अर्थशास्त्रियों की भी राय में जहां पुनर्वितरण तंत्र (redistribution mechanism) मौजूद है (भारत की तरह), तेज विकास से गरीबी कम होगी।<sup>16</sup> इस तरह से तेज विकास के परिदृश्य के आंकलन सच्चाई के काफी करीब हैं। मैं सटीक आंकलन का दावा नहीं करता हूं, लेकिन आंकलन सच्चाई के करीब होने का दावा तो करता ही हूं। चक्रवृद्धि ब्याज की जबर्दस्त ताकत से अर्थशास्त्री वाकिफ हैं, इसीलिए 35 साल में ज्यादा तेज सकल राष्ट्रीय उत्पाद से वास्तविक अनुभव से बेहतर सामाजिक परिणामों ने उन्हें नहीं चौंकाना चाहिए।

## निष्कर्ष (Conclusion)

भारत ने समाजवाद के लंबे खींच गए प्रयोग और विकास को तेज करने वाले सुधारों को लागू करने में देरी के कारण बड़ी सामाजिक त्रासदी झेली। इसका सबसे भयावह परिणाम रहा 1.45 करोड़ शिशुओं की बेवजह मौत। 26.1 करोड़ कम साक्षर और 10.9 करोड़ ज्यादा गरीब भी बुरा ही कहा जाएगा। यह समूची कवायद, उद्देश्य के लिहाज से साधारण है। इसे हकीकत के विरोधाभासी परिदृश्य के अनुसंधान की दिशा में पहले कदम की तरह देखा जाना चाहिए। विभिन्न अनुमानों पर आधारित आंकलन “कम शिशुओं” (Missing Children) की संख्या में कुछ लाख का बदलाव दिखा सकते हैं, लेकिन सभी का निष्कर्ष एक बड़ी मानवीय त्रासदी की ओर ही इशारा करेगा। जनसंख्या विशेषज्ञ एंसले कोल ने अमर्त्य सेन के “लापता महिलाओं” (Missing Women) के आंकलन को 10 करोड़ से 6 करोड़ कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट है। लेकिन इससे सेन के मूल अध्ययन का महत्व या औचित्य कम नहीं हुआ। अगर कोई और विश्लेषक मेरे द्वारा किए गए काम को पूरी मेहनत के साथ दोबारा करता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि समाजवाद 1.45 करोड़ नहीं, बल्कि 1.1 करोड़ बच्चों की मौत का कारण बना, यह बात जस की तस ही खरी रहेगी कि आर्थिक सुधारों में देरी के परिणाम बहुत घातक रहे।

20वीं सदी में ऐसे दुष्ट निरंकुश लोगों की कोई कमी नहीं रही, जिन्होंने जानबूझकर लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा। भारत में ऐसा नहीं हुआ, जहां समाजवादी नेताओं को उनके विरोधी भी उदार और नेकनीयत मानते थे। भारत के समाजवादी तहेदिल से गरीबी का उन्मूलन चाहते थे और ब्रिटिश राज से जुड़ी ऊंची शिशु मृत्यु दर को भी कम करना चाहते थे। उन्हें यकीन था कि उनकी विचारधारा से इसे जल्द हासिल किया जा सकेगा। फिर भी अच्छे उद्देश्य वाली ये नीतियां लाखों बच्चों की मौत का कारण बनीं। वाकई नर्क का रास्ता भी तो नेक इरादों के साथ ही बनाया जाता है।

## नोट्स (Notes)

*इंडिकस एनालिटिका* ने इस अध्ययन में टेबल बनाने में मदद की। मैं यहां उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।

1. स्वामीनाथन एस. अंकलेसरिया अय्यर, *एस्केप फ्रॉम द बेनेवोलेंट जूकीपर्स* (नई दिल्ली: टाइम्स ऑफ इंडिया, 2008), पेज 9
2. देखें अरविंद पनगरिया, *इंडिया, द इमर्जिंग जायंट* (न्यूयॉर्क: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2008) और "द ट्रियम्फ ऑफ इंडियाज मार्केट रिफॉर्म्स: द रिकॉर्ड ऑफ द 1980 एंड 1990," *केटो इंस्टीट्यूट पॉलिसी एनालिसिस* नं. 554, 7 नवंबर 2005
3. इजिप्ट में क्लियोपेट्रा के चेहरे वाले एक सिक्के ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया: शायद वह वास्तविकता में खूबसूरत नहीं थी
4. अमर्त्य के. सेन, "मोर देन 100 मिलियन विमेन आर मिसिंग," *न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स*, 20 दिसंबर 1990
5. अमर्त्य के. सेन, "डेमोक्रेसी एज ए यूनिवर्सल वैल्यू," *जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी*: 10, नं.3 (जुलाई 1999)3-17
6. सेन, "मोर देन 100 मिलियन विमेन आर मिसिंग"
7. स्टीफन डुबनर और स्टीवन लेविट, "द सर्च फॉर 100 मिलियन मिसिंग विमेन," *स्लेट*, 24 मई 2005
8. एमिली ओस्टर, "हेपेटाइटिस बी एंड द केस ऑफ मिसिंग विमेन," *जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकॉनॉमी* 113, नं. 6 (2005) 1163-1216
9. मोनिका दास गुप्ता, "केन बायोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक हेपेटाइटिस बी एक्सप्लेन द बल्क

ऑफ जेंडर इम्बैलेंस इन चाइना? ए रिट्यू ऑफ द एविडेंस," *वर्ल्ड बैंक रिसर्च ऑब्जर्वर* 23, नं. 2 (2008) 201-17

10. एंसले कोल, "एक्सेस फीमेल मोर्टलिटी एंड द बैलेंस ऑफ सेक्सेज इन द पॉपुलेशन: एन एस्टिमेटेड नंबर ऑफ मिसिंग फीमेल्स," *पॉपुलेशन एंड डवलपमेंट रिट्यू* 7, (1991) 517-23

11. इस अध्ययन में आंकड़ों का विश्लेषण सरकारी सूत्रों पर आधारित है। हर साल के आंकड़े उपलब्ध नहीं होते: ऐसे मामलों में missing (लापता या कमी) का आकलन साधारण रूझानों के विश्लेषण से हासिल किए गए। भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद की श्रृंखला, 1999-2000 (राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान, भारत सरकार) के आधार वर्ष काफी स्थिर मूल्यों वाली रही है। इससे पहले के आंकड़े का आधार वर्ष तुलना योग्य नहीं है। मैंने उन्हें इस तरीके से आम तुलना योग्य बनाया: दो साल के बीच के प्रतिशत के योग का आंकलन उस श्रृंखला के आधार पर किया गया, जिसके इन दो वर्षों के आंकड़े मौजूद थे। और फिर प्रतिशत में इस परिवर्तन के आधार पर 1999-2000 के आधार से पहले के सालों का भी आंकलन किया गया। हर दशक के लिए वार्षिक विकास के रूझान का आंकलन संबंधित कालखंड के रूझान (यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लांगेस्ट कमांड के इस्तेमाल से किया गया) के आधार पर किया गया। भारत की जनगणना ने हर दशक के पहले साल की मार्च के पहले सप्ताह की आबादी (1991, 2001 और आगे) की जानकारी दी। बीच के वर्षों की आबादी की गणना दशक की प्रतिशत वृद्धि का वार्षिक आंकलन करके की गई। इससे फिर हर वर्ष की आबादी का आंकलन किया गया। इसी तरह से छह वर्ष के ऊपर की आबादी (भारत में साक्षरता दर छह वर्ष से ऊपर की आयु के आधार पर तय होती है) का अनुमान लगाया गया। योजना आयोग, भारत सरकार के अनुसार आबादी (head count ratio/HCR) का अनुपात ही गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत है। ये आंकड़े पांच साल के अंतर से (1999-2000 वित्त वर्ष में गरीबी के आंकलन को लेकर कुछ विवाद हो गया था, इसलिए उन्हें यहां शामिल नहीं किया गया) उपलब्ध होते हैं। बीच के वर्षों की एचसीआर का आंकलन गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों के प्रतिशत पर आधारित रेखीय (linear) मॉडल से किया गया। गरीबी की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल उत्पाद विकास से मूल्य सापेक्षता का आंकलन 1971-2008 के बीच एचसीआर में रूझान प्रतिशत (trend percentage) के इसी काल में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल उत्पाद विकास के विभाजन से किया गया। इसी तरह से साक्षरता और शिशु मृत्यु दर के रूझान प्रतिशत के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल उत्पाद विकास के रूझान प्रतिशत से आंकलन किया गया।

12. भारत में आर्थिक सुधारों के 1980 की बजाय 1991 में शुरू होने और इससे 80 के दशक में उत्पादकता में भारी इजाफा अब शैक्षिक साहित्य में भी अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है। उदाहरण के लिए, डेनी रोड्रिक और अरविंद सुब्रह्मण्यम, "फ्रॉम 'हिंदू ग्रोथ' टू प्रॉडक्टिविटी सर्ज: द मिस्ट्री ऑफ इंडियन ग्रोथ ट्रांजिशन" नेशनल ब्यूरो ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्च वर्किंग पेपर 10376, मार्च 2004

13. अंतिम वर्ष में भारत की विनिमय दर बहुत ज्यादा अस्थिर थी, एक अमेरिकी डॉलर के लिए 47 रुपए से लेकर 52 रुपए तक। मेरा प्रति व्यक्ति जीएनपी के लिहाज से डॉलर की विनिमय दर का आंकलन 50 रुपए का है।

14. 1970 के दशक में साक्षरता में वास्तविक गिरावट बहुत ज्यादा थी-मेरे तेज विकास के परिदृश्य से भी ज्यादा तेज-1980 के दशक में इसमें हल्का सा सुधार देखा गया। इसी वजह से मेरा मॉडल टेबल में शुरूआती वर्षों में साक्षरता में सुधार को नकारात्मक दिखाता है, बाद में तेजी से सुधार के साथ।

15. सुरजीत भल्ला जैसे विद्वानों ने भारत में गरीबी के आंकलन के तौर-तरीके और सरकारी आंकलन को लेकर विवादों को चुनौती दी है। मैंने उस विवाद में न पड़कर आधिकारिक आंकड़ों का इस्तेमाल किया है।

16. जोसेफ स्टिंगलिट्ज, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स (न्यूयॉर्क: डब्ल्यूडब्ल्यू नॉर्टन, 2002)

कैटो इंस्टीट्यूट डवलपमेंट पॉलिसी ब्रीफिंग पेपर्स सीरीज़ के अंतर्गत हुए अध्ययन  
Studies in the CATO Institute Development Policy Briefing Paper Series

1. *ट्रबलिंग साइन्स फॉर साउथ अफ्रिकन डेमाॅक्रेसी अंडर दि एएनसी*

- मेरियन एल. टुपी (25 अप्रैल, 2007)

2. *केन्याज़ फाइट अगेन्स्ट करप्शन: ऑन अनईवन पाथ टु पोलिटिकल अकाउंटबिलिटी* - जॉन गीथोंगो (15 मार्च, 2007)

3. *ए सेकेंड लुक एट माइक्रोफिनांस: दि सिक्वेन्स ऑफ ग्रोथ एंड क्रेडिट इन इकॉनॉमिक हिस्ट्री* - थॉमस डिचर (15 फरवरी, 2007)

कैटो इंस्टीट्यूट पॉलिसी एनालिसिस सीरीज के अंतर्गत हुए अध्ययन

Studies in the CATO Institute Policy Analysis Series

649. सोमालिया, रिडक्स: ए मोर हैंड्स-ऑफ अप्रोच - डेविड ऐक्स (12 अक्टूबर, 2009)
648. वुड अ स्ट्रिक्टर फेड पॉलिसी ऐंड फाइनांशियल रेग्युलेशन हेव अवर्टेड दि फाइनांशियल क्राइसिस?  
- जगदीश गोखले ऐंड पीटर वन डोरेन (8 अक्टूबर, 2009)
647. व्हाइ सस्टेनबिलिटी स्टैंडर्ड्स फॉर बायोफ्युल प्रोडक्शन मेक लिट्ल इकोनॉमिक सेन्स - हैरी डि गॉर्टे ऐंड डेविड आर. जस्ट (7 अक्टूबर, 2009)
646. हाउ अर्बन प्लेनर्स कॉज्ड दि हाउसिंग बबल - रैंडल ओ'टूले (1 अक्टूबर, 2009)
645. वॉलेजो कॉन डियोस: व्हाइ पब्लिक सेक्टर यूनियनिज़्म इज़ ए बैड डील फॉर टैक्सपेयर्स ऐंड रेप्रेज़ेंटेटिव गवर्नमेंट - डॉन बेल्लंटे, डेविड डेन्होम ऐंड इवान ओसोरियो (28 सितंबर, 2009)
644. गेटिंग वॉट यू पैड फॉर—पेइंग फॉर वॉट यू गेट: प्रपोजल्स फॉर दि नेक्स्ट ट्रान्सपोर्टेशन रिआथोराइजेशन - रैंडल ओ'टूले (15 सितंबर, 2009)
643. हाफ वे टु व्हेयर? आन्सरिंग दि की क्वेश्चन्स ऑफ हेल्थकेयर रिफॉर्म - माइकल टॅनर (9 सितंबर, 2009)
642. फैन्नी मेड? व्हाइ ए "पब्लिक ऑप्शन" इज़ हज़ार्डस टु युवर हेल्थ - माइकल एफ. कॅनन (27 जुलाई, 2009)
641. दि पॉवर्टी ऑफ प्री-स्कूल प्रॉमिसेस: सेविंग चिल्ड्रेन ऐंड मनी विथ दि अर्ली एजुकेशन टैक्स क्रेडिट - एडम बी. शीफर (3 अगस्त, 2009)
640. थिंकिंग क्लियरली अबाउट इकोनॉमिक इनईक्वालिटी - विल विल्किनसन (14 जुलाई, 2009)
639. ब्रॉडकास्ट लोकलिज़्म ऐंड दि लेसन्स ऑफ दि फेअरनेस डॉक्ट्रिन - जॉन सैम्पल्स (27 मई, 2009)
638. ओबामा केयर टु कम: सेवेन बैड आइडियाज़ फॉर हेल्थ केयर रिफॉर्म - माइकल टॅनर (21 मई, 2009)
637. ब्राइट लाइन्स ऐंड बैलआउट्स: टु बैल ओर नॉट टु बैल, दैट इज़ दि क्वेश्चन - वर्न मैकिन्ले ऐंड गेरी गेगेन्हीमर (21 अप्रैल, 2009)
636. पाकिस्तान ऐंड दि फ्यूचर ऑफ यूएस पॉलिसी - मलाओ इनोसेंट (13 अप्रैल 2009)
635. नाटो एट 60: ए हॉलो अलायन्स - टेड गेलेन कारपेंटर (30 मार्च, 2009) 634. फाइनेंशियल क्राइसिस ऐंड पब्लिक पॉलिसी - जगदीश गोखले (23 मार्च, 2009)
633. हेल्थ-स्टेटस इन्श्योरेंस: हाउ मार्केट्स केन प्रोवाइड हेल्थ सिक्योरिटी - जॉन एच. कॉकरेन (18

फरवरी, 2009)

632. ए बेटर वे टु जेनरेट ऐंड यूज कंपॅरटिव इफेक्टिवनेस रिसर्च - माइकल एफ. कॅनन (6 फरवरी, 2009)

631. ट्रबल्ड नेबर: मेक्सिकोज़ ड्रग वॉयलेंस पोज़ेस ए थेट टु दि युनाइटेड स्टेट्स - टेड गेलेन कारपेंटर (2 फरवरी, 2009)

630. ए मॅटर ऑफ ट्रस्ट: व्हाइ कॉंग्रेस शुड टर्न फेडरल लेंड्स इनटू फिड्यूशियरी ट्रस्ट्स - रैंडल ओ'दूले (15 जन्वरी, 2009)

629. अनबेयरेबल बर्डन? लिविंग ऐंड पेइंग स्टूडेंट्स लोन्स एज ए फर्स्ट-ईअर टीचर - नील मैकक्लस्की (15 दिसंबर, 2008)

628. दि केस अगेन्स्ट गवर्नमेंट इंटरवेन्शन इन एनर्जी मार्केट्स: रिविज़िटेड वन्स अगेन - रिचर्ड एल. गोर्डन (1 दिसंबर, 2008)

627. ए फेडरल रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी रिक्वाइर्मेंट: वॉट्स नॉट टु लाइक? - रॉबर्ट जे. माइकेल्स (13 नवंबर, 2008)

626. दि इयूरेबल इंटरनेट: प्रेज़र्विंग नेटवर्क न्यूट्रैलिटी विदाउट रेग्युलेशन - टिमोथी बी. ली (12 नवंबर, 2008)

625. हाइ-स्पीड रेल: दि राँग रोड फॉर अमेरिका - रैंडल ओ'दूले (31 अक्तूबर, 2008)

624. फिस्कल पॉलिसी रिपोर्ट कार्ड ऑन अमेरिकाज़ गवर्नर्स: 2008 - क्रिस एडवर्ड्स (20 अक्तूबर, 2008)

623. टू काइंड्स ऑफ चेंज: कंपेयरिंग दि कॅंडिडेट्स ऑन फॉरिन पॉलिसी - जस्टिन लोगान (14 अक्तूबर, 2008)

622. ए क्रिटीक ऑफ दि नेशनल पॉपुलर वोट प्लान फॉर इलेक्टिंग दि प्रेसीडेंट - जॉन सैंपल्स (13 अक्तूबर, 2008)

621. मेडिकल लाइसेंसिंग: एन ऑब्स्टकल टु अफोर्डबल क्वालिटी केयर - शर्ली स्वॉर्नी (सितंबर 17, 2008)

620. मार्केट्स वर्सेस मोनोपॉलीज़ इन एजुकेशन: ए ग्लोबल रिव्यू ऑफ दि एविडेन्स - एंड्र्यू जे. कोल्सन (10 सितंबर, 2008)

619. एग्जिक्युटिव पे: रेग्युलेशन वर्सेस मार्केट कॉम्पिटिशन - इरा टी. के. ऐंड स्टीवन वैन पुटेन (10 सितंबर, 2008)

618. दि फिस्कल इम्पेक्ट ऑफ ए लार्ज-स्केल एजुकेशन टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम - एंड्र्यू जे. कोल्सन विथ ए टेक्निकल अपेंडिक्स - एन्का एम. कोटेट (1 जुलाई, 2008)

617. रोडमैप टु ग्रिडलॉक: दि फेल्योर ऑफ लॉग-रेंज मेट्रोपॉलिटन ट्रान्स्पोर्टेशन प्लानिंग - रैंडल ओ'टूले (27 मई, 2008)
616. डिस्मल साइन्स: दि शॉर्टकॉमिंग्स ऑफ यू.एस. स्कूल चॉय्स रिसर्च ऐंड हाउ टु अड्रेस देम - जॉन मेरिफील्ड (16 अप्रैल, 2008)
615. डज रेल ट्रान्ज़िट सेव एनर्जी ऑर रेड्यूज ग्रीनहाउस गॅस एमिशनस? - रैंडल ओ'टूले (14 अप्रैल, 2008)
614. ऑर्गन सेल्स ऐंड मॉरल ट्रेवल्स: लेसन्स फ्रॉम दि लिविंग किडनी वेंडर प्रोग्राम इन ईरान - बेंजामिन ई. हिप्पेन (20 मार्च, 2008)
613. दि ग्रास इज नॉट ऑल्वेज ग्रीनर: ए लुक एट नेशनल हेल्थकेयर सिस्टम्स अराउंड दि वर्ल्ड - माइकल टॅनर (18 मार्च, 2008)
612. इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लायमेंट एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन: फ्रॅन्ज़ काफकाज़ सॉल्यूशन टु इल्लेगल इमिग्रेशन - जिम हार्पर (5 मार्च, 2008)
611. पार्टिंग विथ इल्युजन्स: डिवेलपिंग ए रियलिस्टिक अप्रोच टु रिलेशनस विथ रशिया - निकोलस ग्वॉस्टेव (29 फरवरी, 2008)
610. लर्निंग दि राइट लेसन्स फ्रॉम इराक - बेंजामिन एह. फ्रीडमन, हार्वी एम. सेपोल्स्की ऐंड क्रिस्टोफर प्रेबल (13 फरवरी, 2008)
609. वॉट टु डू अबाउट क्लाइमेट चेंज - इंडुर एम. गोकलेनी (5 फरवरी, 2008) 608. क्रॅक्स इन दि फाउंडेशन: नाटोज़ न्यू ट्रबल्स - स्टॅन्ली कोबर (15 जनवरी 2008)
607. दि कनेक्शन बिट्वीन वेज ग्रोथ ऐंड सोशल सिक्यूरिटीज़ फाइनेंशियल कंडीशन - जगदीश गोखले (10 दिसंबर, 2007)
606. दि प्लैनिंग टॅक्स: दि केस अगेन्स्ट रीजनल ग्रोथ-मॅनेजमेंट प्लैनिंग - रैंडल ओ'टूले (6 दिसंबर, 2007)
605. दि पब्लिक एजुकेशन टैक्स क्रेडिट - एडम बी. शीफर (5 दिसंबर, 2007) 604. ए गिफ्ट ऑफ लाइफ डिज़र्व्स कॉम्पन्सेशन: हाउ टु इनक्रीज लिविंग किडनी डोनेशन विथ रियलिस्टिक इन्सॅटीक्स - आर्थर जे. मेटास (7 नवंबर, 2007)
603. वॉट कॅन दि युनाइटेड स्टेट्स लर्न फ्रॉम दि नॉरडिक मॉडेल? - डॅनियल जे. मिचेल (5 नवंबर, 2007)
602. डू यू नो दि वे टु एल.ए.? सैन जोस शोज़ हाउ टु टर्न एन अर्बन एरिया इनटू लॉस एंजिसि इन थ्री स्ट्रेसफुल डेकेड्स - रैंडल ओ'टूले (17 अक्टूबर, 2007)

601. दि फ्रीडम टु स्पेंड युवर ओन मनी ऑन मेडिकल केयर: ए कॉमन कैज़ुअल्टी ऑफ यूनिवर्सल कवरेज - केंट मास्टरसन ब्राउन (15 अक्टूबर, 2007)

600. ताइवान्ज़ डिफेन्स बजट: हाउ ताइपेईज़ फ्री राइडिंग रिस्कस वॉर - जस्टिन लोगान एंड टेड गेलेन कारेपेंटर (13 सितंबर, 2007)

599. एंड इट, डोन्ट मैन्ड इट: वॉट टु डू विथ नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड - नील मैकक्लस्की एंड एंड्र्यू जे. कोल्सन (5 सितंबर, 2007)

598. डोन्ट इनक्रीज़ फेडरल गैसोलीन टैक्सेस— अबॉलिश देम - जैरी टैलर एंड पीटर वैन डोरेन (7 अगस्त, 2007)

## CENTER FOR GLOBAL LIBERTY & PROSPERITY

### बोर्ड ऑफ एडवाइज़र्स BOARD OF ADVISORS

एनी एपल्बऑम, *वॉशिंगटन पोस्ट*  
गुरचरण दास, पूर्व सीईओ, *प्रॉक्टर*  
*एंड गैम्बल (इंडिया)*

अरनॉल्ड हारबर्गर, *यूनिवर्सिटी*  
*ऑफ कॅलिफॉर्निया, लॉस एंजेलिस*

फ्रेड हू, *गोल्डमन सैक्स एशिया)*

पेद्रो-पाब्लो कुकज़िन्स्की, *पेरू के*  
*पूर्व प्रधानमंत्री*

दीपक लाल, *यूनिवर्सिटी ऑफ*  
*कॅलिफॉर्निया. लॉस एंजेलिस*

जोस पिनेरा, *पूर्व श्रम और*  
*सामाजिक सुरक्षा मंत्री. चिली*

सेंटर फॉर ग्लोबल लिबर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी की स्थापना विकासशील देशों के सामने खड़ी आम समस्याओं के खुले-बाजार आधारित हल खोजने के उद्देश्य से की गई। सेंटर का ऐसी नीतियों पर जोर होता है जो मानवाधिकारों का संरक्षण करते हों और ज्यादा निजी विकल्प उपलब्ध कराने के साथ गरीबी के खात्मे में आर्थिक आजादी की भूमिका का भी समर्थन करे। आर्थिक विकास से जुड़े मसलों पर सेंटर के विशेषज्ञों का ध्यान होता है। इसमें आर्थिक विकास, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकट, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, नीतियों में सुधार, सरकारी सहायता एजेंसियों की उपयोगिता, सार्वजनिक पेंशन का निजीकरण, समाजवाद से बाजारवाद में परिवर्तन और वैश्वीकरण शामिल हैं।

सेंटर फॉर ग्लोबल लिबर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें वेबसाइट:

[www.cato.org/economicliberty/](http://www.cato.org/economicliberty/).

## डेवलपमेंट पर केटो इंस्टिट्यूट के अन्य अध्ययन

### OTHER STUDIES ON DEVELOPMENT FROM THE CATO INSTITUTE

"एन इंटरनेशनल मोनेटरी फंड करेंसी टू राइवल द डॉलर? व्हाय स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स कांट प्ले दैट रोल?"-स्वामीनाथन एस. अंकलेसरिया अय्यर, डवलपमेंट पॉलिसी एनालिसिस नं. 10 (7 जुलाई, 2009)।

"द फाल्स प्रॉमिस ऑफ ग्लेनईगल्स: मिसगाइडेड प्रॉयरिटीज एट द हार्ट ऑफ द न्यूपुश फॉर अफ्रीकन डवलपमेंट"-मेरियन एल. टूपी, डवलपमेंट पॉलिसी एनालिसिस नं. 9 (24 अप्रैल, 2009)।

"एलसाल्वाडोर: एन अमेरिकन टाइगर?"-जुआन कार्लोस हिडाल्गो, डवलपमेंट पॉलिसी एनालिसिस नं. 8 (9 मार्च, 2009)।

"बेनेफिट ऑफ पोर्ट लिबरलाइजेशन: ए केस स्टडी फ्रॉम इंडिया"-स्वामीनाथन एस. अंकलेसरिया अय्यर, डवलपमेंट पॉलिसी एनालिसिस नं. 7 (3 दिसंबर, 2008)।

"जिम्बाब्वे: फ्रॉम हायपरइंफ्लेशन टू ग्थ"-स्टीव एच. हैंक, डवलपमेंट पॉलिसी एनालिसिस नं. 6 (25 जून 2008)।

"ए डिडेड ऑफ सफरिंग इन जिम्बाब्वे: इकानॉमिक कोलेप्स एंड पॉलिटिकल रिप्रेशन अंडर रॉबर्ट मुगाबे"-डेविड कोलटार्ट, डवलपमेंट पॉलिसी एनालिसिस नं. 5 (24 मार्च, 2008)।

"फिफटीन ईयर्ज ऑफ ट्रान्स्फर्मेशन इन दि पोस्ट-कम्यूनिस्ट वर्ल्ड: रॅपिड रिफॉर्मर्स आउटपरफॉर्मर्ड ग्रेजुलिस्ट्स"-ओलेह हेविरलशिन, डवलपमेंट पॉलिसी एनालिसिस नं. 4 (9 नवंबर, 2007)।

"सिक्वोरिंग लैंड राइट्स फॉर चाइनीज फार्मर्स: ए लीप फॉर्वर्ड फॉर स्टेबिलिटी ऐंड ग्थ"-ज्यू केलियांग ऐंड रॉय प्रोस्टरमेन, डवलपमेंट पॉलिसी एनालिसिस नं. 3 (15 अक्टूबर, 2007)।



Nothing in this Development Briefing Paper should be construed as necessarily reflecting the views of the Center for Global Liberty and Prosperity or the Cato Institute or as an attempt to aid or hinder the passage of any bill before Congress. Contact the Cato Institute for reprint permission. Additional copies of Development Briefing Paper are \$6 each (\$3 for five or more). To order, contact the Cato Institute, 1000 Massachusetts Avenue, N.W., Washington, DC, 20001, (202) 842-0200, fax (202) 842-3490, [www.cato.org](http://www.cato.org).